>

Title: Introduction of the Right to Information (Amendment) Bill, 2019 (Division held and Bill introduced)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): मैं प्रस्ताव करता हूं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रो. सौगत राय जी, डॉ. शशि थरूर जी और अधीर रंजन चौधरी जी, आप लोगों ने जो नोटिसेज दिए हैं, वह बिल के पुनर्स्थापन के विरोध के कारण दिए गए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इसमें कोई लेजिस्लेटिव रूप से विरोध नहीं किया गया है। आप बिल की चर्चा के दौरान भी इस विषय को उठा सकते हैं। मैं फिर भी आपको आसन की विशेष व्यवस्था के तहत एक-एक मिनट बात कहने का मौका दे रहा हूं।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राइट टू इन्फार्मेशन एक्ट लाया गया है, यह हमारी रूल्स के मुताबिक नहीं लिया गया I would like to draw your attention that under Rule 74 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, it has been stated:

> "Provided further that no such motion shall be made until after copies of the Bill have been made available for the use of Members, and that any Member may object to any such motion being made unless copies of the Bill have been so

made available for two days before the day on which the motion is made and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the motion to be made."

Sir, I am referring to Kaul & Shakdher. At page mo. 66, it states:

"A Bill is not included in the List of Business for introduction until copies of the Bill have been made available to Members at least two days before the day on which it is proposed to be introduced."

Sir, this requirement is waived by the Speaker in respect of Appropriation Bill. माननीय मंत्री जी राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल को इंट्रोड्यूज कर रहे हैं, हमें इसके लिए दो दिन का मौका नहीं दिया गया। यह रूल्स के मुताबिक नहीं हुआ है। मंत्री जी बिल में जो संशोधन लाना चाहते हैं, वह हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सूचना का अधिकार फंडामेंटल मतलब मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को हनन करने की कोशिश हो रही है। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल में प्रपोज किया जा रहा है in terms of salaries, in terms of service, emoluments, duration of tenure, information commission etc. पहले इलैक्शन कमीशन का पांच साल का फिक्स टेन्योर था, अब यह सरकार तय करेगी। Salaries, allowances and other terms of service was same as Election Commission and for Election Commission, it is same as the Judges of the Supreme Courts and the High Courts.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप डिटेल में बोल रहे हैं। आप बिल पर क्या बोलेंगे? इस बिल को लाने की आपत्ति पर सवाल उठाइए।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री अधीर रंजन चौधरी : हम चाहते हैं कि कमीशन पर सरकार का हस्तक्षेप न रहे। यह सरकार कमीशन पर हस्तक्षेप करना चाहती है। इसके ऊपर दबाव डालना चाहती है। इनकी फ्रीडम, आजादी को खत्म करना चाहती है।... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: आप चर्चा न करें। एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : In fact, the Standing Committee opined that the Information Commission is an important creation under the Act.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, 19बी में यह अनुमति दी है।

श्री सौगत राय जी।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं फिर आग्रह कर रहा हूं कि आप बिल की आपत्ति के समय पूरे बिल पर चर्चा करने लग जाते हैं।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: आप मेरी बात सुन लीजिए। यहां एन.के. प्रेमचन्द्रन जी तथा अन्य विद्वान बैठे हैं। इस तरह से हर बिल पर बिना लेजिस्लेटिव कानून के तहत कोई बात, जिसमें ऑब्जेक्शन करने का तर्क हो, उसके बिना ही आपत्ति प्रदान करने लग जाएंगे तो सदन चलने वाला नहीं है। मेरा आप सबसे आग्रह है, आप जब भी बोलते हैं, पूरे बिल पर ही चर्चा करने लग जाते हैं। आप अपनी बात उठाएं, विधेयक को पुर:स्थापित करने के विरोध का पक्ष उठाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सदन आपका है, लेकिन पूरे बिल पर चर्चा न करें।

श्री सौगत राय।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: I have a last line. There are several issues which require urgent attention of the Government to ensure proper functioning of the RTI Act including making appointment to fill large number of vacancies in the Information Commission etc, … (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): With all the force at my command, I beg to oppose the introduction of Right to Information (Amendment) Bill.

Sir, I may mention in this context that in the 15th Lok Sabha, 71 per cent of the Bills were sent to parliamentary scrutiny. In the 16th Lok Sabha, that number has dropped. It was only 26 per cent of the Bills that were sent for parliamentary scrutiny. In the present Lok Sabha, … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: यह विषय इसमें कहां आ गया?

…(<u>व्यवधान</u>)

प्रो. सौगत राय : यह कनैक्टिड है। …(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

…(<u>व्यवधान</u>)

प्रो. सौगत राय: माननीय अध्यक्ष जी, आप मेरे बोलने के बीच में मंत्री जी को बुला रहे हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सौगत राय जी, मैं मंत्री जी के बाद आपको बुलाऊंगा ।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री जी को अधिकार है ।

…(<u>व्यवधान</u>)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): At the time of introduction, if they want to oppose, let them

oppose it on the legislative competency of the Bill and not on the merit of the Bill. They are discussing the merit of the Bill. They can discuss the merit of the Bill in the debate.

माननीय अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दे चुका हूं, इसी व्यवस्था पर माननीय सदस्यों को चलना है, नहीं तो अगला नाम पुकारा जाएगा।

…(<u>व्यवधान</u>)

प्रो. सौगत राय: मैंने सुना है, लेकिन मैंने तो अभी बोलना शुरू ही नहीं किया है। ये प्राब्लम है कि नए पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर हैं। …(व्यवधान) यह नए हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह चार बार के लोकसभा के सदस्य रहे हैं, नए नहीं हैं।

…(<u>व्यवधान</u>)

PROF. SOUGATA RAY : I have opposed the introduction of the Bill. …(*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: Do you want this Bill to be referred to the Standing Committee then?

PROF. SOUGATA RAY: I oppose the introduction of the Bill. … (*Interruptions*) Sir, in this present Parliament, not even one of the 11 Bills has been referred to the Standing Committee for their opinion. … (*Interruptions*) Sir, if the Parliamentary Affairs Minister decides to disturb a Member in this way, I expect you to protect me from disruption. आप मुझे संरक्षण दीजिए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सदन में बताएं कि इस बिल का इंट्रोडक्शन से क्या संबंध है? अगर इस पर डिटेल में चर्चा करनी है तो आप नोटिस दीजिए। मैं उस पर चर्चा कराऊंगा।

…(<u>व्यवधान</u>)

प्रो. सौगत राय: महोदय, मैं आपसे संरक्षण मांगता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अभी आप बिल इंट्रोडक्शन पर बोलें।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: महोदय, राइट टू इन्फार्मेशन बहुत ही जरूरी अधिकार है। पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी ने कहा –

> "Information Commission is an important creation under the Act, which will execute the laudable scheme of the legislation."

Now, this Bill seeks to renew the power of the Information Commission because the earlier Bill said that the Central Information Commission will have the same power as that of the Election Commission. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर जी।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : आप मुझे बोलने दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप इसका जवाब दें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर जी की ही बात रिकॉर्ड में जाएगी ।

...(व्यवधान) *

माननीय अध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर, क्या आप बोलना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर जी की बात ही नोट हो रही है।

...(व्यवधान) *

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, the entire framework of the Right to Information Act depends on the independence and autonomy of the Information Commissions, both the State and the Central Information Commissions. The Standing Committee that studied the original RTI Bill recommended insulating these bodies. It recommended providing statutory terms and fixed salaries in the same way as the Election Commission, and this was accepted by the Parliament in the RTI Bill.

By removing the statutory terms, by making it subject to the Government's wishes based on the Government's rule making powers and by taking over the power, the Bill is removing the two greatest armours. …(*Interruptions*) Sir, please understand, I am not talking about the merits. It is not an RTI (Amendment) Bill. It is an RTI Elimination Bill. This Bill is removing the two greatest armours of institutional independence and on top of that, by controlling the State Information Commissioners, by taking over the power to determine their salaries, the Central Government is destroying it. …(*Interruptions*)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I have given a notice under Rule 72. I am of the opinion that this Bill lacks legislative competence. Sir, as you know very well--you are a learned person sitting on the august Chair--that in our Constitution, we have article 246 which defines the Union and State Lists; and the Concurrent List is in Schedule VII of the Constitution. Why I say it lacks competence is because clause 3 amends Section 16 of the principal Act. This abrogation takes away the powers of the State. That is why, I say that this Bill lacks competence. Now, clause 3 violates schemes set up under article 246. The Union is not competent to legislate on matters of access to records

and information under the subjects and entries that fall under the State List. …(*Interruptions*) I request you to please listen to me.

माननीय अध्यक्ष : केवल माननीय जितेन्द्र सिंह जी का भाषण नोट होगा।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्लीज, मैंने भी बिल को पूरा पढ़ा है।

…(<u>व्यवधान</u>)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, विडम्बना यह है कि बिना बिल पर चर्चा हुए, शायद बिना उसको पूरी तरह से पढ़े हुए, माननीय सदस्य इस पर अपनी निष्कर्ष एवं टिप्पणियां दे रहे हैं। I may not be as learned as Owaisi ji and Prof. Sougata Ray are, but I am trying to learn from all of them. And, for my learning, I understand that they would let it get introduced now, and when it is taken up for consideration, they may discus each of the points which they have raised threadbare. Short of that, if they want me to respond, then it will amount to just responding to the entire discussion. …(*Interruptions*)

DR. SHASHI THAROOR : It can be sent to the Standing Committee.

DR. JITENDRA SINGH: Even if it has to be sent to the Standing Committee, we have to have the reasons for doing that. … (*Interruptions*)

Now, let me tell you one thing. I do not want to get into discussion because then it will amount to replying to the Bill-discussion as such.अब यह कहा जा रहा है कि इसमें कम्पिटेंसी नहीं है, यह बिल सर्कुलेट ही नहीं हुआ। This amounts to challenging the decision and the authority of the hon. Speaker's Chair. बिल सर्कुलेट हुआ । अध्यक्ष जी ने यह मुनासिब समझा कि इसको इन्ट्रोडक्शन के लिए लाया जाए। आप यह भी मानने को तैयार

नहीं हैं। आप बताइए इसका क्या उत्तर है? इसके बाद यह कहा जा रहा है कि आप उनकी सैलरीज में दखल दे रहे हैं। बिल तो यह कह रहा है कि आरटीआई एक्ट में रूल बनाने का प्रावधान नहीं था। We are just trying to introduce that. I will come to it in the course of discussion. We will also discuss on the amendment which authorises the Government to frame the rules. सैलरी कितनी हुई है, इसकी तो अभी चर्चा ही नहीं हुई। सारे जमाने में जिसका जिक्र नहीं था, वह बात इन पर बड़ी नागवर गुजरी है। How has Owaisi ji assumed that we are reducing the salaries? यह तो चर्चा में होगी। …(व्यवधान) Thirdly, Shashi Tharoor ji has rightly pointed out that it is a statutory body. Now, if we accept that it is a statutory body, then let it be a statutory body. …(*Interruptions*) Let me complete.…(*Interruptions*)

Sir, they are law knowing persons. But without being a law-knowing person, I will just read out to you a number of judgements which I thought would not come handy in the introduction of the Bill itself. What is the difference between a statutory tribunal or statutory commission and a judiciary body on the other hand? I refer to the Judgement in the case of State of Gujarat vs. Gujarat Revenue Tribunal. …(*Interruptions*) उस विषय पर भी आते हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों को मौका देता हूं। आप बार-बार खड़े होंगे तो इस तरीके से चेयर से परमिशन नहीं मिलेगी। आप इन्टरप्ट न करें।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री असादुद्दीन ओवैसी : आप हमको बोलने नहीं देते हैं।

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको पूरा मौका देता हूं।

…(<u>व्यवधान</u>)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, क्योंकि यह बिल अभी इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर है, केवल धारणा दूर करने के लिए, यह तय हो चुका है। It has been debated in the Court of Law, not once but time and again, that:

> "An authority may be described as a quasi-judicial authority if it possesses certain attributes. But it cannot be taken as a court."

So, this is a statutory body. How can you equate it with the Supreme Court? How can you equate it with an elected body? I do not want to go into all this because we have a lot of time to discuss it.

A person manning a tribunal or a commission in this case cannot claim parity or privileges at par with a High Court judge or, in this case, with a Supreme Court judge, not even a High Court judge. This is from Chandra Kumar vs. Union of India of 1997. So, these are the things in which I am not going today in detail. I will get into it later.

Let me now come back to it.

As far as Modi Government is concerned, हमारी प्रतिबद्धता पर कोई अंगुली न उठाए, कोई संदेह न करे। आपको याद होगा, वर्ष 2014 में सरकार बनने के तुरन्त बाद प्रधान मंत्री जी ने हमे यह मंत्र दिया था 'Maximum Governance, Minimum Government'. उसके लिए पारदर्शिता, नागरिक भागीदारी और ईज ऑफ गवर्नेंस अनिवार्य है। This amendment is meant to bring about institutionalisation of RTI Act, streamlining of RTI Act and ease of delivery. On the contrary to what you are saying, this is rather going to strengthen the RTI structure as such. There is no interference with the RTI. अब हुआ यह है, जो मैं कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैंने सोचा पहले दिन से ही विवाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें इस पर दो दिन झगड़ा करना है। या तो उत्साह था जल्दी-जल्दी आर.टी.आई. बनाने का या

शायद समय का अभाव था, इसलिए नियम बनाए ही नहीं गए। अब इसमें हमारा क्या कसूर है। हम तो प्रायश्चित कर रहे हैं…(व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Parliament should make the rules and not you. …(*Interruptions*)

DR. JITENDRA SINGH: We have come to the Parliament. …(*Interruptions*) No, I am not yielding. …(*Interruptions*) You are the Parliament. We have come to you. Are you not Parliament? You tell me. अब उस अफरा-तफरी में नियम बनाए ही नहीं गए और यह अधिकार भी नहीं रखा कि नियम बनाने हैं कि नहीं बनाने। So, we are bringing an amendment. In other words, to put it in brief, I would say that this is rather an enabling legislation for administrative purposes.

जहां तक यह कहा गया कि कंसलटेशन ही नहीं हुई, due consultation was done with the Legal Affairs Department, the Legal Department. अब यह कहा जा रहा है कि…(व्यवधान) आपके पास आए है, तभी तो इंट्रोड्यूज करवा रहे हैं। कंसलटेशन के लिए ही तो आए हैं। हमने पिछले पांच साल में आर.टी.आई. एक्ट को और ज्यादा प्रभावी बनाने का प्रयास किया है। हमने आर.टी.आई. का पोर्टल बना दिया। आप क्या छोडकर गए थे? 10 से 5 आर.टी.आई. होती थीं। आज आपको अपने मोबाइल एप से 24 घंटों में कभी भी ज्ञानोदय होता है तो आप आर.टी.आई. कर सकते हैं। यह हमने पांच साल में किया है। हम पर कौन आरोप लगा सकता है कि हमने आर.टी.आई. को कमजोर किया है। हमने इसको ऑनलाइन किया। इसे आज देश-विदेश में बैठे हुए कर सकते हैं। Section 4 of the RTI Act आप लाए थे which says '*suo motu* sharing of information in the public domain' वह नहीं हो रहा था, आज देखिए हमारी वेबसाइट्स इतनी सुचारू है। डी.ओ.पी.टी. में भी किसी अधिकारी का आर्डर होता है तो उसको उसकी प्रति बाद में पहुंचती है, उससे पहले वेबसाइट्स पर आ जाती है। नई बिल्डिंग हमने बनाई। आप कह रहे है कि आर.टी.आई. पहले प्रभावी था। एक ऐसा समय भी आया कि चार-चार सदस्यों

के साथ कमीशन चलता था, आपके जमाने में तो ऐसा नहीं हुआ, फिर एक ऐसा समय आया कि एक लीडर ऑफ दी अपोजिशन होना चाहिए। There should be Leader of Opposition in the Selection Committee. We walked an extra mile. हमने कहा कि कांग्रेस को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मिला तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। हमने कहा let the Leader of the largest opposition party be a member. हमने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को आमंत्रित किया, उसके बाद भी आप कह रहे हैं, So, let the Bill be introduced. जो भी होगा, हम डिसकसन करेंगे और मैं खुले दिल से कहता हूं, We are bringing in this amendment to authorise the Government to frame rules. उसमें आपके जो भी सुझाव होंगे कि किस तरह की सैलेरी होगी, किस तरह का टेन्योर होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: You send it to the Standing Committee.

DR. JITENDRA SINGH: No. Why should we? Let us first discuss.

You tell me how you can justify this anomaly. The Central Information Commissioner and the Information Commissioner are equivalent to a judge of the Supreme Court. …(*Interruptions*) Please listen. …(*Interruptions*) Owaisi *saheb*, the problem is that you react before listening to the whole sentence. उसकी अगर जजमेंट को चेलेंज करना हो तो आप हाईकोर्ट को चैलेंज करते हैं। क्या कभी दुनिया भर में ऐसा हुआ? सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल की जजमेंट को अपोज किया जा रहा है। That is the Act you have made. You have made a clumsy Act and we are trying to modify it. This is a clumsy Act and it is done in a haste. You gave the Information Commissioner the status of a Supreme Court and at the same time, left the provision of appeal to the High Court. इसका कोई जवाब देगा। हम उसमें सुधार ला रहे हैं।…(*Interruptions*) Shashiji, I am saying this with an open mind. …(*Interruptions*) I am not contesting

what you are saying. We are having an open mind. In order to improve upon this, as I said, to streamline it and to make it more institutionalised, we will incorporate it, but we have to correct these anomalies.

Suddenly, we cannot do it. …(*Interruptions*). We have come to the Parliament to ask for the power. …(*Interruptions*).

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, I want Division. … (*Interruptions*)

<u>12.40 hrs</u>

At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri Sudip Bandyopadhyay, Kunwar Danish Ali, Shri E.T. Mohammed Basheer, Shri Mohammed Faizal and some other hon. Members left the House.

माननीय अध्यक्ष: प्रवेश-कक्ष खाली कर दिए जाएं –

अब प्रवेश-कक्ष खाली हो गए हैं।

ANNOUNCEMENT RE: DIVISION

माननीय अध्यक्ष : महासचिव।

महासचिव : माननीय सदस्यगण, मुझे आपको यह सूचित करना है कि चूंकि सदस्यों को अभी तक मत विभाजन संख्या का आबंटन नहीं किया गया है। अत: स्वचालित मतदान रिकार्डिंग मशीन द्वारा मत-विभाजन कराना संभव नहीं है।

अब मत-विभाजन नियम 367 एए के अंतर्गत पर्चियों के वितरण द्वारा किया जाएगा।

सदस्यों को अपने मत दर्ज करने के लिए उनके स्थान पर 'हां' या 'नही' मुद्रित पर्चियां दी जाएंगी। 'हां' वाली पर्चियां हरे कागज पर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में एक ओर छापी गई हैं और 'नहीं' वाली पर्चियां पीछे गुलाबी कागज पर छापी गई हैं। सदस्य पर्चियों पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर और अपना नाम, पहचान पत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एवं तिथि साफ अक्षरों में लिखकर अपनी पसंद का मत दर्ज करें। जो सदस्य 'मतदान में भाग न लेने वाला' मत दर्ज कराना चाहते हैं, वे 'मतदान में भाग न लेने वाली' पीले कागज में छापी गई पर्ची मांग सकते हैं। अपना मत दर्ज करने के तत्काल बाद प्रत्येक सदस्य अपनी पर्ची मत विभाजन अधिकारी को देंगे, जो उनके स्थान पर उन पर्चियों को लेने आएंगे तथा उन्हें सभा पटल के अधिकारियों को सौंप देंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे मत-विभाजन के लिए केवल एक पर्ची को ही भरें।

सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि मत-विभाजन अधिकारियों द्वारा पर्ची एकत्र किए जाने के पश्चात् ही अपना स्थान छोड़ें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान दी जाए।"

श्री असादुद्दीन ओवैसी: सर, डिविजन ।

माननीय अध्यक्ष : अब मतदान ।

<u>लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:</u>

-

<u>DIVISION</u> **<u>AYES</u>** **<u>12.50 hrs</u>**

Agrawal, Shri Rajendra

Ahluwalia, Shri S.S.

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Anuradha, Shrimati Chinta

Bachegowda, Shri B.N.

Baheria, Shri Subhash Chandra

Balyan, Dr. Sanjeev

Bapat, Shri Girish Bhalchandra

Barne, Shri Shrirang Appa

Basavaraj, Shri G. S.

Beniwal, Shri Hanuman

Bey, Shri Horen Sing

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhargava, Shri Ramakant

Bhatia, Shri Sanjay

Bhatt, Adv. Ajay

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bidhuri, Shri Ramesh

Bisen, Dr Dhal Singh

Bisoyi, Shrimati Pramila

Bista, Shri Raju

Bohra, Shri Ramcharan

Chahar, Shri Rajkumar

Chatterjee, Shrimati Locket

Chaudhary, Shri P. P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Pradeep Kumar

Chaudhuri, Sushri Debasree

Chauhan, Shri Devusinh

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Shri Bhagirath

Choudhary, Shri Chandra Prakash

Chouhan , Shri Nihal Chand

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji

Damor, Shri Guman Singh

Das, Shri Pallab Lochan

Delkar, Shri Mohanbhai Sanjibhai

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna

Devendrappa, Shri Y.

Devi, Shrimati Annpurna

Devi, Shrimati Rama

Dharmapuri, Shri Arvind

Diler, Shri Rajveer

Dubey, Dr. Nishikant

Dubey, Shri Vijay Kumar

Duggal, Sushri Sunita

Firojiya, Shri Anil

Gaddigoudar, Shri P. C.

Gadkari, Shri Nitin Jairam

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gao, Shri Tapir

Ghosh, Shri Dilip

Gogoi, Shri Topon Kumar

Gupta, Shri Sangam Lal

Hemamalini, Shrimati

Hembram, Shri Kunar

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jadav, Dr. Umesh G.

Jadon, Dr. Chandra Sen

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

Jolle, Shri Annasaheb Shankar

Joshi, Shri C. P.

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kaswan, Shri Rahul

Katara, Shri Kanakmal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Khan, Shri Saumitra

Kher, Shrimati Kirron

Kishore, Shri Kaushal

Koli, Shrimati Ranjeeta

Kotagiri, Shri Sridhar

Kotak, Shri Manoj

Kumar, Dr Virendra

Kumar, Shri Bandi Sanjay

Kumar, Shri Narendra

Kumar, Shri P. Raveendranath

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Vijay

Kumari, Sushri Diya

Kushwaha, Shri Ravindra

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Mahtab, Shri Bhartruhari

Mahto, Shri Baidyanath Prasad

Majhi, Shri Ramesh Chandra

Majumdar, Dr. Sukanta

Mallah, Shri Kripanath

Mallick, Dr. Rajashree

Mandal, Shri Ajay Kumar

Mandal, Shri Ramprit

Mandal, Shrimati Manjulata

Mandavi , Shri Mohan

Mane, Shri Dhairyasheel Sambhajirao

Maurya, Dr. Sanghamitra

Meena, Shrimati Jaskaur

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mendhe, Shri Sunil Baburao

Mohan, Shri P. C.

Munda, Shri Arjun

Munde, Dr. Pritam Gopinathrao

Muniswamy, Shri S.

Munjapara , Dr.(Prof.) Mahendra

Murmu, Kumari Chandrani

Murmu, Shri Khagen

Nagar, Shri Rodmal

Naik, Shri Shripad Yesso

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Praveen Kumar

Oja, Shrimati Queen

Pachauri, Shri Satyadev

Pal, Shri Krishan

Pandey, Shri Santosh

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Kamlesh

Patel (Bakabhai), Shri Mitesh

Patel, Dr.K.C

Patel, Shri Devaji

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh

Patel, Shri Hasmukhbhai Somabhai

Patel, Shri R.K. Singh

Patel, Shrimati Keshari Devi

Patel, Shrimati Sharda Anil

Pathak, Shri Subrat

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Pawar, Dr. Bharati Pravin

Pfoze, Dr. Lorho

Pintu , Shri Sunil Kumar

Pujari, Shri Suresh

Rai, Shri Nityanand

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Ram, Shri Vishnu Dayal

Rana, Shrimati Navneet Ravi

Ranjan, Dr R. K.

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathva, Shrimati Gitaben V.

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Rawat, Shri Ashok Kumar

Reddeppa, Shri N.

Reddy, Shri G. Kishan

Roy, Dr. Rajdeep

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahoo, Shri Mahesh

Sahu, Shri Chandra Sekhar

Sai, Shrimati Gomati

Saikia, Shri Dilip

Saini, Shri Nayab Singh

Sangma, Kumari Agatha K.

Sao, Shri Arun

Sarangi, Shri Pratap Chandra

Sarangi, Shrimati Aparajita

Saraswati, Shri Sumedhanand

Sarkar, Dr. Subhas

Sarkar, Shri Jagannath

Saruta, Shrimati Renuka Singh

Seth, Shri Sanjay

Sethi, Shrimati Sarmistha

Shah, Shri Amit

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi

Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shri Jugal Kishore

Sharma, Shri Vishnu Datt

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul Ramesh

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shrangare, Shri Sudhakar Tukaram

Shyal, Dr. Bharatiben D.

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Singh ' Lalan', Shri Rajiv Ranjan

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh(Retd.) , Gen. Dr V. K .

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Shri Arjun

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijendra

Singh, Shri Dharambir

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Mahabali

Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Rajbahadur

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shrimati Kavita

Sinha, Shri Jayant

Solanki, Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai

Solanky, Shri Mahendra Singh

Soni, Shri Sunil Kumar

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Soren, Shri Sunil

Subba, Shri Indra Hang

Suman, Dr. Alok Kumar

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya

Teli, Shri Rameswar

Thakur , Shri Gopal Jee

Thakur, Shri Anurag Singh

Tripathi, Dr. Ramapati Ram

Tripura, Shri Rebati

Tudu, Er. Bishweswar

Tumane, Shri Krupal Balaji

Uikey, Shri Durga Das

Vardhan, Dr. Harsh

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha Arun

Yadav, Shri Giridhari

Yadav, Shri Krishna Pal Singh

Yadav, Shri Mulayam Singh

Yadav, Shri Ram Kripal

Yepthomi, Shri Tokheho

NOES

Jaleel, Shri Syed Imtiaz

Natarajan, Shri P.R.

Owaisi, Shri Asaduddin

Pasunoori, Shri Dayakar

Pothuganti, Shri Ramulu

Reddy, Shri Kotha Prabhakar

Thirumaavalavan, Dr. Thol

Vasanthakumar, Shri H.

Venkatesan, Shri S.

ABSTAIN

Nil

माननीय अध्यक्ष: मत विभाजन का परिणाम यह है:

हाँ: 224

नहीं : 9

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक पुर:स्थापित करें ।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ ।

माननीय अध्यक्ष: प्रवेश कक्ष खोल दिया जाए ।

-

12.59 hrs